ducted on the premises of unauthorised travel agents in coordination with law and order authorities; touts and anti-social elements have been rounded up. Door to door checks have been conducted, reply paid letters have been issued to ascertain the genuineness of reservation demands and intensive checks have been organised on trains to cross check the antecedents of the passengers actually travelling with the details given in the requisition slips.

विकलांगों के लिये कालेज शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की योजना

*112. **श्री निहाल सिंह :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग विद्यार्थियों के लिये इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, झांसी और आगरा के इंटरमीडिएट कालेजों में शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु शत प्रतिशत सहायता प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार को एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० यूंथन) : (क) से (ग). अगस्त, 1977 में उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग छात्रों के लिये लखनऊ में दो इंटरमीडियेट कालेजों और आगरा तथा कानपुर प्रत्येक में एक एक कालेज में क्रियान्विति के लिये समेकित शिक्षा प्रारंभ करने हेतु एक प्रस्ताव पेश किया था। यह योजना शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना थी और भारत सरकार ने सितम्बर, 1977 में 76,800 रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी। 1978-79 के दौरान राज्य सरकार इस निधि का उपयोग न कर सकी और इस प्रकार 1978-79 के दौरान इस स्वीकृति को पुनः अभिपुष्ट किया गया। फिर भी 1-4-79 से योजना की वित्तीय पद्धति को बदल दिया गया और केन्द्र तथा राज्य के बीच उसे आधा-आधा (50/50) कर दिया गया। चूंकि राज्यों ने नई पद्धति के अधीन योजना की क्रियान्विति में दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिये 1-4-81 से शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना की पुरानी पद्धति को बहाल किया गया। तदनुसार मार्च, 1981 में सभी राज्यों से अनुरोध किया गया था कि संशोधित पद्धति के अधीन वे अपने प्रस्ताव भेजें जैसे ही राज्य सरकार अपने प्रस्ताव भेज देगी वैसे ही उत्तर प्रदेश के लिये योजना को स्वीकृति दे दी जायगी। इस मामले का नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा है।

एशियाई खेलों के दौरान भिक्षावृत्ति के समस्या के रूप में प्रकट होने की आशंका

*113. **श्री तारिक अनवर :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में, विशेष कर दिल्ली में भिखारियों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 7 जून, 1982 के **नव भारत टाइम्स** में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भिखारियों को एशियाई खेलों के दौरान भीख मांगने के लिये विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कार्य में किन्हीं सुसंगठित गिरोहों का हाथ होने का संदेह है ;